HRA Sazette of India

असाधारण

EXTRAORDINA !!

भाग II — ७०इ ३ — उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार सं प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364] No. 364] नई दिल्ली, बुधवार, और 😥, 2006/चैत्र 29, 1928

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2006/CHAITRA 29, 1928

गृह यंत्रस्वय

अधिसृचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

का आ. 55% अ).—कन्द्रोय सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ संयुक्त राज्य अमरीका में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में समन ा। वारंट की तामील या उसके निष्पादन के लिए समझौता किया है और अनः केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उप-धारा (1) के खंड (3) के अनुसरण में यह निदेश करती है कि —

- (क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम समन, या
- (ख) किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट, या
- (ग) किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाला ऐसा कोई समन कि वह हाजिर हो और कोई दस्तातेज या अन्य चीज पेश करे अथवा उसे पेश करे. या

(घ) तलाशी वारंट

भारत में किसी न्यायालय द्वारा दो प्रतियों में उस देश में प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार रखने वाले न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को संयुक्त राज्य अमरीका में केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से उस न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को यह निदेश देते हुए भेजा जा सकेगा कि वह ऐसे समन की तामील या ऐसे वारंट का निष्पादन उसमें नामित्त व्यक्ति पर करे।

2. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि ऐसा समन या वार्ट संयुक्त राज्य अमरीका के केन्द्रीय प्राधिकारी को भेजे जाने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा।

डा. पी. के. सेंठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS SOUFICATION

Tipa Delhi, the 19th April, 2006

S.O. 553(E)—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the United States of America for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters, on any person in the United States of America, and therefore, in pursuance of clause (ii) of sub-section (1) of section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that -

- (a) a summons to an accused person, or
- (b) a warrant for the arrest of an accused person, or
- (c) a summons to any person requiring him to attend and produce document or other thing, or to produce it, or
- (d) a search warrant,

may be issued by a Court in India in duplicate, to the Court, Judge or Magistrate having authority, under the law in force in that country, through the Central authority in the United States of America directing that Court, Judge or Magistrate to serve such summons or execute such warrant on the person named therein.

2. The Central Government further directs that such summons or warrant shall be sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Central authority in the United States of America.

(F. No. 2/1/2006-Judi. Cell (i)) Dr. P. K. SETH, Jt. Seev

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

का.आ. 554(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रायुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ संयुक्त राज्य अमरीका में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या सरकार ने निष्पादन के लिए समझौता किया है अतः केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उपधारा (1) के अनुसरण में, यह निदेश देती है कि किसी आवराधिक मामले में अन्वेषण या जांच के दौरान किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में किसी स्थान पर तामील या निष्पादित किए जाने वाले, यथास्थिति, समन या वारंट, इससे उपाबद्ध, यथास्थिति, प्ररूप 'क' या प्ररूप 'ख' में जारी किए जाएंगे और ऐसे समन या वारंट संयुक्त राज्य अमरीका में केन्द्रीय प्राधिकारी को पारेषित किए जाने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे।

प्ररूप-क साक्षी को समन (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 105ख की उपधारा (2) देखिए)

प्रेषिती,
······································
 (संयुक्त राज्य अमरीका में केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से)
मेरे समक्ष यह परिवाद किया गया है कि(अभियुक्त का नाम) (पता)
(समय और स्थान सहित अपराध क
संक्षेप में उल्लेख कीजिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि) उसने अपराध किया है, औ
मुझे यह प्रतीत होता है कि यह संभावना है कि आप अभियोजन के लिए तात्विक साक्ष्य दे
सकते हैं या कोई दस्तावेज या अन्या चीज पेश कर सकते हैं ;

को न्यायसंगत हेतुक के बिना हाजिर होने में उपेक्षा करेंगे या रूससे इंकार करेंगे, तो आपको हाजिर कराने के लिए वारंट जारी किया जाएगा

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश/मजिख्द्रेट के हस्ताक्षर

प्ररूप ख साक्षी को लाने के लिए वारंट (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 105ख की उपधारा (2) देखिए)

प्रेषिती संयुक्त राज्य अमरीका में न्यायालय/न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट, (संयुक्त राज्य अन्योका में केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से)

भेरे सम्ब्र आवेदन किया गया है कि(अभियुक्त का नाम और
वर्णन)(पता) ने
(समय और स्थान रहित अपराध का संक्षिप में उल्लेख कीजिए) का अपराध किया है या संदेह है
कि उसमें किया है, और मुझे यह प्रतीत होता है कि वह संभावना है कि(साक्षी का
नाम और वर्णन) अभियोजन के लिए तात्विक साक्ष्य देगा या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश
करेगा और उक्त कार्यी आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है और
मेरे पाल विश्वास करने का ठोरा और पर्याप्त कारण है कि वह उक्त मामले के अन्वेषण या जांच में
जब तक हाजिर नहीं होगा तब तक कि उसे ऐसा करने के लिए विवश न किया जाए ;
मुझेयह अनुरोध करता है और इसके द्वारा में यह अनुरोध करता हूँ कि
उपर्युक्तं कारणों हे और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए आप उक्त(व्यक्ति का
नाम) को गिरफतार कराएंगे और गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी
की अभिरक्षा में भेजेंगे ।
तारीख़200 को गरे हस्ता क्षर से और न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रदत्त किया गया ।
न्यायालय की मुद्रा न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट

[फा. सं. 2/1/2006-न्या. सेल (ii)] डा. पी. के. संट, संयुक्त सचिव

To

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

S.O. 554(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the United States of America for services or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in the United States of America, and therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that a summons or warrant, as the case may be, for attendance of a person during the investigation or inquiry in any criminal case, to be served or executed in any place in the United States of America shall be issued in Form A or Form B annexed hereto, as the case may be, and such summons or warrant shall be sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Central Authority in the United States of America.

FORM A

SUMMONS TO WITNESS [See sub-section (2) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973]

		•				
(Through the Central	Authority	in the Unite	ed States	of Ame	rica)

Whereas an application has been made before me that (Name of the accused) of (address) has (or is suspected to have) committed the offence of (state the offence concisely with time and place) and it appears to me that you are likely to give material evidence or to produce any document or other thing for the prosecution;

	You are h	nereby summoned to	ap	opear befo	ore the	Court on t	he		d	ay
of	next	atAM/PM	to	produce	such	document	or	thing	ог	to

depart then without the order of the Court, and you are hereby warned that, if you shall without just cause neglect or refuse to appear on the said date, a warrant will be issued to compel your attendance.

Seal of the Court

Signature of the Judge/Magistrate

FORM - B

WARRANT TO BRING UP A WITNESS

[See sub-section (2) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973]

To

The Court America,

/Judge/Magistrate in the United States of

(Through the Central Authority in the United States of America)

Given under my hand and the seal of the Court this-----day of --

-----200

Seal of the Court

Signature of the Judge/Magistrate

[F. No. 2/1/2006-Judl. Cell (ii)]
Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

का.आ. 555(अ).—केन्द्रीय सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ संयुक्त राज्य अमरीका में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या उसके निष्पादन के लिए समझौता किया है अतः केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उपधारा (1) के अनुसरण में, यह निदेश देती है कि भारत में किसी न्यायालय का किसी व्यक्ति को हाजिर करने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए गिरफ्तारी के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के किसी स्थान में निष्पादित किया जाने वाला वारंट इससे उपाबद्ध प्ररूप में जारी किया जाएगा और ऐसा वारंट दो प्रतियों में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को संयुक्त राज्य अमरीका में केन्द्रीय प्राधिकारी को अग्रेषित किए जाने के लिए भेजा जाएगा ।

प्ररूप

(साक्षी को लाने के लिए वारंट) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 105ख देखिए

प्रेषिती,

संयुक्त राज्य अमरीका में न्यायालय/न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट (संयुक्त राज्य अमरीका के केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से)

और मेरे पास यह विश्वास करने का ठोस और पर्याप्त कारण है कि वह तब तक हाजिर नहीं होगा/होगी या निम्नलिखित दस्तावेज या अन्य चीजें पेश नहीं करेगा/करेगी जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए विवश न किया जाए :

(i) (यहां उन दस्तावेजों या चीजों की सूची दें जो पेश की जानी हैं)

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर [फा. सं. 2/1/2006-न्या. सेल (iii)] डा. पी. के. सेट, संयुक्त सचिव

William Branch erfaltwar & la .

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

s.o. 555(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the United States of America for services or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in the United States of America, and therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central

Government hereby directs that a warrant from a Court in India for arrest of a person to attend or produce a document or other thing, to be executed in any place in the United States of America shall be issued in the Form annexed hereto and that such warrant shall be sent in duplicate to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Central Authority in the United States of America.

FORM

WARRANT TO BRING UP A WITNESS

See section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973

To

The Court/Judge or Magistrate in the Government of the United States of America.

(Through the Central Authority, the United States of America)

Whereas complaint has been made before me that (name and description of the accused) of (address) has (or is suspected to have) committed an offence of (mention the offence concisely), and it appears to me that (name and description of witness) is likely to give evidence concerning the said complaint; and, whereas, it appears that the said witness is residing within the local limits of your jurisdiction;

And whereas, I have good and sufficient reason to believe that he/she will not attend or produce the following documents or other things unless compelled

to do so:

(i) (Here give the list of documents or things to be produced)

I,------, have the honour to request and hereby do request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to cause the said (Name of the witness) to be arrested and also require such person to produce the document or thing listed above, which may be in his/her possession and to forward the person in custody alongwith the documents or things to the undersigned through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this----- day of ------ 200

Seal of the Court

Signature of the Judge/Magistrate

JF. No. 2/1/2006-Judl. Cell (iii)]
Dr P. K. SETH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

का.आ. 556(अ).— केन्द्रीय सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ संयुक्त राज्य अमरीका में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या उनके निष्पादन के लिए समझौता किया है, अत: अब केन्द्रीय सरकार. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उपधारा (2) के अनुसरण में संयुक्त राज्य अमरीका के ऐसे सक्षम न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को, जिसे उस देश में प्रवृत्त विधि के अधीन किसी अभियुक्त व्यक्ति को समन या किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट या किसी व्यक्ति के हाजिर होने और कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने अथवा उसे पेश करने की अपेक्षा करने वाला समन जारी करने के लिए प्राधिकार है, ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जो आपराधिक मामलों के संबंध में भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों को समन जारी कर सकेगा।

2. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि ऐसी दशा में जहां संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से प्राप्त समन या तलाशी वारंट का निष्पादन किया गया है, वहां पेश किए गए दस्तावेज और चीजें या तलाशी के दौरान मिली चीजें, समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय को पारेषित किए जाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में केन्द्रीय प्राधिकारी को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भेजी जाएंगी।

[फा. सं. 2/1/2006-न्या. सेल (iv)] डा. पी. के. सेट, संयुक्त सचिव

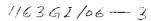
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

S.O. 556(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the United States of America for services or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in the United States of America, and therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies competent Court, Judge or Magistrate in the United States of America having authority, under the law in force in that country, to issue a summons to an accused person, or a warrant for the arrest of an accused person, or summons to any person requiring him to attend and produce a document or other thing, or to produce it, as the Court by which such summons or warrant may be issued to persons residing in India in relation to criminal matters.

2. The Central Government further directs that in a case where a summons or a search warrant received from the Government of United States of America has been executed, the documents or things produced or things found in the search shall be forwarded to the Court issuing the summons or search warrant through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority in the United States of America.

[F No. 2/1/2006-Judl, Cell (iv)]
Dr P K SETH, Jt. Secv.



अधिस्चना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

का.आ. 557(अ).— केन्द्रीय सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ भारत के न्यायालयों में आपराधिक मामलों के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका में निवास कर रहे ताक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए समझौता किया है, अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 285 की उपधारा (3) के अनुसरण में निदेश देती है कि

- (क) संयुक्त राज्य अमरीका में साक्षियों की परीक्षा के लिए कमोशन भारत के न्यायालयों द्वारा इससे उपाबद्ध प्ररूप में संयुक्त राज्य अमरीका के किसी सक्षम दण्ड न्यायालय को, जिसे संयुक्त राज्य अमरीका में प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त है, जारी किया जाएगा ; और
- (ख) ऐसा कमीशन संयुक्त राज्य अमरीका में केन्द्रीय प्राधिकारी को पारेषित किए जाने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा । प्ररूप

भारत से बाहर साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन (दण्ड प्रक्रिया-संहिता 1973 की धारा 285 की उपधारा (3) देखिए)

न्यायालय

प्रेषिती
(गृह मंत्रालय, भारत रारकार, नई दिल्ली के माध्यम से)
मुझे यह प्रतीत होता है कि लियालय मामला संख्या
बनाममेंका साक्ष्य न्याय के उद्देश के लिए आवश्यक है और ऐसा सार्क्ष
आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है तथा उसकी हाजिरी
अयुक्तियुक्त विलम्ब, व्यय या असुविधा के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, अत
भें अप रो अनुरोध क रता है कि आप उपरोक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की
सहायता के लिए उक्त साक्षी को ऐसे समय और स्थान पर, जो आप नियस करें, हाजिर होने वं
समन और ऐसे साक्षियों की परीक्षा उने परिग्रश्नों (मौखिक परीक्षा के लिए) के आधार प
oरवा एं जो इस कमीश न के साथ भेजे जा रहे हैं :

कार्यवाही का कोई पक्षकार आपके समक्ष अपने काउन्सेल या अभिकर्ता के माध्यम से या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो व्यैक्तिक रूप में हाजिर हो सकेगा और उक्त साक्षी की (यथास्थिति), परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनःपरीक्षा कर सकेगा;

और मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप उक्त साक्षी के उत्तरों को लेखबद्ध कराए और ऐसी सभी बहियों, पत्रों, कागजों और दस्तावेजों को, जो ऐसी परीक्षा के दौरान पेश किए जाएं, पहचान के लिए सम्यक् रूप से चिन्हित कराएं और आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप ऐसी परीक्षा को अपनी सरकारी मुद्रा और अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करें और उसे इस कमीशन के साध अधोहस्ताक्षरी को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भेजें।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख......2006 को प्रदत्त किया गया ।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

[फा. सं. 2/1/2006-न्या. सेल (v)]

डा. पी. के. सेट, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

S.O. 557(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the United States of America for taking the evidence of witnesses residing in the United States of America in relation to criminal matters in Courts in India, and, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that -

(a) Commission for examination of witnesses in the United States of America shall be issued by the Courts in India in the Form annexed hereto, to any competent Criminal Court of the United States of America having authority under the law in force in the United States of America; and

(b) such Commission shall be sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority in the United States of America.

FORM

COMMISSION TO EXAMINE WITNESS OUTSIDE INDIA

[See sub-section (3) of section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973]

IN THE COURT OF	-
То	
(Through the Ministry of Home Government of India, New Delhi.)	Affairs,

Any party to the proceeding may appear before you by his/her Counsel or agent or, if not in custody, in person, and may examine, cross-examine or reexamine (as the case may be) the said witness;

And, I, further have the honour to request that you will be pleased to cause the answers of the said witness to be reduced into writing and all books, letters, papers and documents produced upon such examination to be duly marked for identification and that you will be further pleased to authenticate such examination by your official seal and signature and to return the same together with this Commission to the undersigned through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this ----- day of------

Seal of the Court

Signature of the Judge/Magistrate

[F. No. 2/1/2006-Judl. Cell (v)]
Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

अधि ुत्रना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

का.आ. 558(अ).—केन्द्रीय सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ संयुक्त राज्य अमरिका में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या उनके निष्पादन के लिए समझौता किया है, अतः अब केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 290 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में संयुक्त राज्य अमरीका में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले ऐसे सभी न्यायालयों, न्यायाधीशों, या मिजस्ट्रेटों को जिन्हें संयुक्त राज्य अमरीका में प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त है, ऐसे न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिनके द्वारा भारत में निवास कर रहे साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जा सकेगा।

[फा. सं. 2/1/2006-न्या. सेल (vi)] डा. पी. के. सेट, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

S.O.558(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the United States of America for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in the United States of America and therefore, in pursuance of clause (b) of subsection (2) of section 290 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies all Courts, Judges or Magistrates exercising jurisdiction in the United States of America having authority, under the law in force in the United States of America as the Courts by whom Commission for the examination of witnesses residing in India may be issued.

[F No. 2/1/2006-Judi. Cell (vir)]
On P. K. SETH, Jr. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, १० अप्रैल, २००६

का.आ. 559(अ).—केन्द्रीय सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ संयुक्त राज्य अमरीका में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में समन या दारंट की तामील या उनके निष्पादन के लिए समझौता किया है, अतः, केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त संहिता के अध्याय 7क के उपबंध संयुक्त राज्य अमरीका के संबंध में बिना किसी शर्त, अपदाद या प्रतिबंध के इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लाग होंगे।

[फा. सं. 2/1/2006-न्या. सेल (vii)] डा. पी. के. सेट, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

S.O. 559(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the United States of America for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in the United States of America and, therefore, in exercise of the powers conferred by section 105L of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that the provisions of Chapter VIIA of the said Code shall apply without any condition, exception or qualification in relation to the United States of America with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 2/1/2006-Judl. Cell (vii)] Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.